

DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI ARVIND NETAM): On behalf of Shri D. F. Yadav, I beg to lay on the Table—

- (1) A copy of the Annual Report of the Indian Institute of Science, Bangalore for the year 1974-75. [Placed in Library. See No. LT—10318/76].
- (2) A statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying simultaneously the Hindi version of the above Report. [Placed in Library. See No. LT—10319/76].

11.04 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

- (i) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill, 1976, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 27th January, 1976."
- (ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Pondicherry Appropriation Bill, 1976, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th January, 1976, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."
- (iii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure

and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 2nd February, 1976, agreed without any amendment to the Assam Sillimanite Limited (Acquisition and Transfer of Refractory Plant) Bill, 1976, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th January, 1976."

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMENDMENT) BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table of the House the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill, 1976, as passed by Rajya Sabha.

11.05 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED ACCIDENT IN BELLAMPALI COAL MINE RESULTING IN DEATH OF SOME MINERS.

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur): I call the attention of the Minister of Energy to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

"The reported accident on the 28th January, 1976 in Bellampali mine of the Singareni collieries, resulting in the death of 5 miners and injury to several others."

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI K. C. PANT): I regret to inform the House that according to the information received from the Singareni Collieries Co. Ltd. (a public sector undertaking under the Government of Andhra Pradesh), on the 28th January, 1976 at about 10.30 P.M. in the 2nd incline of Bellampali Colliery there was an accident due to a massive roof fall, measuring, 13 metres/4.5 metres

[Shri K. C. Pant]

average/2.5 metres thick, killing three workers on the spot. Two others who were trapped, were rescued and removed to the hospital but succumbed to the injuries on 29-1-1976. Senior officers of the Company, including the Chairman-cum-Managing Director visited the Colliery immediately. An ex-gratia payment of Rs. 500/- each was given to the families of the deceased workers. The compensation amount, according to the Workmen's Compensation Act, would be paid shortly to the deceased families. The Directorate General of Mines Safety has enquired into the accident and their final report is awaited. I am sure the House will join me in conveying our deep sympathies to the bereaved families.

सरदार स्वर्ण सिंह (सोबी) यह बड़े घफमोस की बात है कि चमनाला की दुर्घटना के फौरन बाद सिधेनी कोलियरीज में यह एक्सिडेंट हुआ है। इस की जिम्मेदारी लेबर मिनिस्टर और एनर्जी मिनिस्टर दोनों पर है। मुझे खुशी है कि लेबर मिनिस्टर साहब भी हाउस में मौजूद है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनक्लाइन में यह जो एक्सिडेंट हुआ है, क्या उस से पहले डायरेक्ट्रेट-जेनरल आफ माइन्ज सेफ्टी द्वारा इस माइन का पीरियाडिकल चैक होता था। क्या मैनेजमेंट के सेफ्टी डिपार्टमेंट ने भी कभी इस को चैक किया था? क्या कम्प्लेक्सन पुराने रेट पर दिया जायेगा? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या 500 रुपये का एक्सपेंडिचर पेमेंट काफी है और क्या इस से वर्कर्स की फैमिलीज की देख-भाल हो सकती है। मेरे पास यह बी० सी० सी० एन० की 1973-74 की एनुअल रिपोर्ट है। इस के पेज 25 पर मैनेजमेंट और डेबिलपमेंट वर्गरेड के बारे में सभी बातें कही गई हैं, लेकिन उस से सेफ्टी का नाम तक भी नहीं है।

माइन्ज की सेफ्टी की जिम्मेदारी सिर्फ डायरेक्ट्रेट जेनरल आफ माइन्ज सेफ्टी के

उपर छोड़ देना उचित नहीं है। क्या मैनेजमेंट की भी यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह अपनी माइन्स की सेफ्टी का ध्यान रखे? मिनिस्टर साहब ने कहा है कि डायरेक्ट्रेट-जेनरल आफ माइन्स सेफ्टी ने इस दुर्घटना के बारे में एनक्वायरी की है। उस एनक्वायरी से क्या होगा? क्या सरकार ने कोई एनक्वायरी कराई है या नहीं और क्या वह कोई एनक्वायरी करने जा रही है। डायरेक्ट्रेट-जेनरल आफ माइन्ज सेफ्टी का तो पता चल गया है कि वे लोग कितना झुंझा काम करते हैं। असमाला में अभी तक मिर्फ पचास लाशें निकल सकी है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य सवाल पूछे।

सरदार स्वर्ण सिंह सोबी मैं यह जानना चाहता हूँ कि माइन्स माइन्स की सेफ्टी के लिए सरकार क्या प्राविजन कर रही है। बिहार में रानीगंज में जो माइन्ज बन्द हुई है क्या वे बन्द रहेंगे? इस तरह के एक्सिडेंट्स को रोकने के लिए सरकार क्या इन्तजाम कर रही है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: जैसा कि मैं ने कहा है, सिधेनी कोलमाइन्ज आन्ध्र प्रदेश सरकार के नीचे है। हम ने वहा से पूरी सूचना मगाई है। इस एक्सिडेंट के बारे में हम को सूचना देने के लिए आज उस के चैयरमैन खुद आये है। उनसे आफिसर्स ने जो एनक्वायरी की थी, उस से यह मालूम पडा कि एक्सिडेंट के दस दिन पहले जेनरल-मैनेजर ने कोलियरी का इन्स्पेक्शन किया, जो ग्राम तौर किया जाता है। कोलियरी मैनेजर रोज इन्स्पेक्शन करता था। उन्होंने उस रोज भी इन्स्पेक्शन किया था। साधारणतया जो इन्स्पेक्शन हुआ करते हैं, वे इस कोलियरी में हुए थे। उस के बावजूद यह एक्सिडेंट हो गया। उस में एक फाल्ट था। जहा पर कोयला निकाला जा रहा था, वह जगह नहीं थी।

बल्कि वहाँ जाने के लिए ओ गैलरी भी उस में बह कूपर से रुफ गिरी। उस में जी डी जी एम एस की एनक्वैरी हुई है उस की घभी जो प्रेलिमिनरी रिपोर्ट आई है उस में भी किसी की जिम्मेदारी नहीं रखी गई है। उस में उन्होंने कहा है कि --

"The accident appears to be a misadventure; the accident is due to the factors beyond human control."

यह घभी प्रेलिमिनरी रिपोर्ट है डी जी एम एस की, फाइनल नहीं है। फाइनल रिपोर्ट जब तक न आ जाये तब तक मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन आज जो एक रिपोर्ट आई है उसके उन में यह बात कही गई है। तो घभी तक तो इस में किसी की जिम्मेदारी की बात नहीं आती है।

जहा तक कम्पेंसेशन का प्रश्न है यह 500 रुपया तो ऐडवाक घभी दिया गया है एक्स-प्रेजिया पेमेंट और 7 हजार रुपया हर परिवार को दिया जायेगा। जो वर्कमें कम्पेंसेशन एक्ट है उस से ज्यादा यह रकम है। उसी के हिसाब से कोई लकीर के फकीर बनने की बात नहीं है, उस से ज्यादा वेगे इसके अलावा वर्कमें भी कुछ कांट्रीब्यूट कर रहे हैं कोलियरी माइन के वर्कमें भी 5 रुपया फो वर्कमें कांट्रीब्यूट कर के दे रहे हैं जो उन को दिया जायेगा। मैनेजमेंट की तरफ से 7 हजार रुपया हर परिवार को दिया जायेगा।

आप ने पूछा कि डी जी एम एस के अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं तो हमने भी एक इंटर्नल सेफ्टी आर्गनाइजेशन पब्लिक सेक्टर कोल माइन में बनाया है और वह टर्नल सेफ्टी आर्गनाइजेशन काम करने लगा है। उस में बाहेर बह कम्पनी के स्तर पर हो या एरिया के स्तर पर या कोलियरी के स्तर

पर हो, प्रोडक्शन स जिस का कोई सम्बन्ध नहीं हो ऐसे सेफ्टी इम्प्लिकेशन निकुल, किये गये हैं जिनको पीछे आ कर माइन्स को इम्पूव् कराना होता है और जिनको बताना, क्या है कि क्या-क्या चीजों की देखरेख करे जिस से ऐक्सीडेन्स न हों।

SOME HON. MEMBERS rose—

MR. SPEAKER: No more questions.

11 22 hrs.

ESTIMATES COMMITTEE

REPORT EIGHTY-EIGHTH AND MINUTES
 SHRI TULSIDAS DASAPPA
 (Mysore) : I beg to present the following Report and Minutes of the Estimates Committee:—

- (i) Eighty-eighth Report on the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms)—Deputation of Indian Experts and Officers abroad.
- (ii) Minutes of the sittings of the Committee relating to the above Report.

11 22½ hrs.

STATEMENT RE APPOINTMENT OF COMMISSION OF INQUIRY TO ENQUIRE INTO ALLEGATIONS AGAINST THE FORMER CHIEF MINISTER AND SOME MINISTERS OF TAMIL NADU.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : As the House is aware, allegations of corruption, favouritism, administrative and financial improprieties and abuse of official position, were being received against the erstwhile Ministry of Tamil Nadu for some time. In November, 1972, Shri M. G. Ramachandran, M.L.A. of Tamil Nadu